शहरी समाचार
नई सोच नई पहल

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार का प्रकाशन

अगस्त, 2021 | मासिक | 10वां अंक | **नगरीय बुलेटिन** | पृष्ठ : 12 | मूल्य : नि:शुल्क

योजना एक नजर में

12,432
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन

74,678
PMAY आवासों का निर्माण पूर्ण

23,274
पीएम स्वनिधि ऋण वितरित

24,659
मुख्यमंत्री श्रमिका योजना (MSY) जॉब कार्ड वितरित

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

DAY-NULM
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission

आत्मनिर्भर भारत

प्रमुख आलेख...

स्वयं सहायता समूह के संवर्धन, सशक्तिकरण एवं नए समूह के गठन के लिए पूरे राज्य में SHG सप्ताह का आयोजन।

प्रधानमंत्री ने राजधानी रांची में निर्माणाधीन LHP के प्रगति की ड्रोन कैमरा के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा की।

पारदर्शिता की ओर बढ़ाएं कदम, जवाबदेही का मूल्य अपनाएं हम।
PMAY (U) के तहत सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया शुरु

इस अंक में

प्रधानमंत्री ने राजधानी रांची में निर्माणाधीन **LHP** के प्रगति की ड्रोन कैमरा के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा की

स्वयं सहायता समूह के संवर्धन, सशक्तिकरण एवं नए समूह के गठन के लिए पूरे राज्य में ''**SHG** सप्ताह'' का आयोजन

डे-एनयूएलएम योजना के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

कोरोना काल में काम न मिलने से थे बोरोजगार, **MSY** ने जीवन किया साकार

टाउन वेंडिंग समिति **(TVC)** के सदस्यों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि से मिलेगा सहयोग

प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करेगा रांची नगर निगम

पीएम स्वानिधि ने जगाई नई आस, योजना का लाभ बढ़ा रहा है लोगों का आत्मविश्वास

जमशेदपुर अक्षेस की नई पहल : जिओ टैगिंग के माध्यम से हल होंगी स्ट्रीट लाइट व चापाकल की समस्याएं

PMAY (U) से हुआ जीवन का अधूरा सपना पूरा

पारदर्शिता की ओर बढ़ाएं कदम, जवाबदेही का मूल्य अपनाएं हम

मछुवा समुदाय के **250** परिवारों के जीवन में बहार बनकर आई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना

MSY ने श्रमिकों की तकदीर व शहर की तस्वीर बदली

बासुकिनाथ नगर पंचायत ने की ''जल शक्ति अभियान'' की शुरुआत

12 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ऋण प्रक्रिया की समीक्षा

कोयले का प्रचुर भंडार एवं पर्यटन की अपार संभावना : चतरा नगर परिषद

अब बिना होल्डिंग नंबर वाले को भी मिलेगा पानी का कनेक्शन : जमशेदपुर अक्षेस

संदेश

नगरीय प्रशासन निदेशालय के "शहरी समाचार" का नवीन अंक निदेशालय के न्यूज लेटर की श्रृंखला का दसवां अंक है। इस न्यूज लेटर के माध्यम से हमने विगत नवम्बर, 2021 से अनवरत राज्य के सभी स्थानीय निकायों से जुड़ी छोटी-बड़ी गतिविधियों को समाहित करने का प्रयास किया है। "शहरी समाचार" का आगाज कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान ही शुरु हुआ था। वर्तमान में भी मानव सभ्यता इस वैश्विक महामारी से पूरी तरह से निजात नहीं पा सकी है। ऐसे में नगरीय प्रशासन निदेशालय अपने सभी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अपनी मुख्य भूमिका को पूर्ण करने के साथ-साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए भी संबंधित प्रबंधन का कार्य कर रहा है। विगत माह तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निदेशाल व राज्य के सभी नगर निकायों के लिए उपलब्धियों की अवधि साबित हुआ है। "शहरी समाचार" के अगस्त, 2021 के अंक में राज्य के सभी स्थानीय निकायों की प्रमुख गतिविधियां- प्रधानमंत्री ने राजधानी राँची में निर्माणाधीन LHP के प्रगति की ड्रोन कैमरा के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा की, प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करेगा रांची नगर निगम, डे-एनयूएलएम योजना के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्यभर में 'SHG सप्ताह' का आयोजन, जमषेदपुर अक्षेस की नई पहल : जिओ टैगिंग के माध्यम से हल होंगी स्ट्रीट लाइट व चापाकल की समस्याएं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) आदि से संबंधित अन्य गतिविधियों को समाहित किया गया है। वर्तमान में राज्य में मानसून की अच्छी बारिश होने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की चुनौतियों में बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है, लेकिन इसके साथ-साथ बारिश की फुहार हम सब में ऊर्जा और उत्साह का भी संचार कर रही है। इस अवधारणा के साथ मैं अपनी सभी सहयोगी संस्थाओं को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने की अपील करती हूं। साथ ही आशा करती हूं कि "शहरी समाचार" का यह अंक हम सभी के लिए प्रेरणादायक एवं लाभकारी साबित होगा।

विजया जाधव
निदेशक,
नगरीय प्रशासन निदेशालय।

पीएम मोदी ने ड्रोन कैमरे से देखा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य

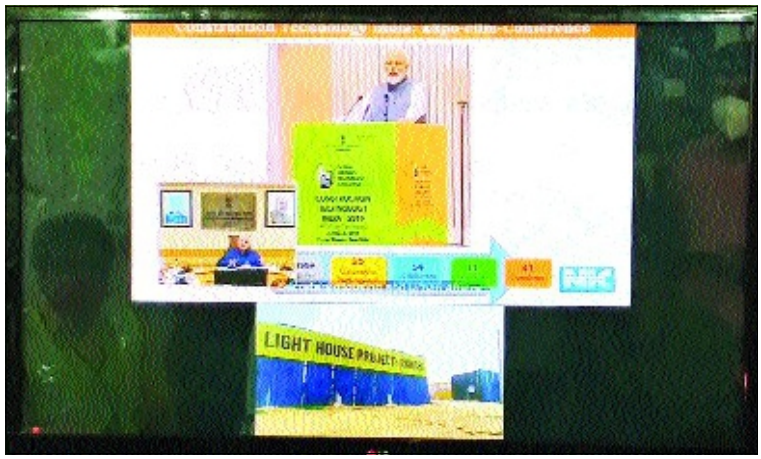

प्रधानमंत्री ने राजधानी रांची में निर्माणाधीन LHP के प्रगति की ड्रोन कैमरा के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा की

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विगत 3 जुलाई, दिन शनिवार को झारखण्ड सहित देश के 6 राज्यों में चल रही लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा की गई। इस दौरान उन्हें राजधानी राँची में निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में ड्रोन कैमरे से जमीनी हकीकत की जानकारी दी गई।

राँची के धुर्वा में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 गरीबों का आशियाना बनाया जा रहा है। धुर्वा के सेक्टर-01, पंचमुखी मंदिर के पास निर्माणाधीन परियोजना स्थल पर ऑनलाइन समीक्षा कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के सचिव श्री विनय चौबे, नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव व नगर आयुक्त मुकेश कुमार के अलावा जिला प्रशासन और रांची नगर निगम के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए।

लाइट हाउस प्रोजेक्ट की निर्माण एजेंसी एसजीसी मैजिक्रीट (Manufacturing Agency SGC Magicrite) के प्रतिनिधि की ओर से परियोजना के संबंध में ड्रोन कैमरा और कंसोल सेटअप के माध्यम से इस किफायती आवास परियोजना के निर्माण की प्रगति एवं पूरी प्रक्रिया से प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया।

निर्माण कार्य का जायजा लेते नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे।

आधुनिकतम तकनीक के जरिए हो रहा है निर्माण कार्य

राँची के लाइट हाउस प्रजेक्ट का निर्माण Precast Concrete Construction System - 3D Volumetric Technology की नवीनतम तकनीक से किया जा रहा है। इस तकनीक से पूरी आवासीय इकाई का ढांचा एक साथ तैयार होता है जिससे ईंट और अन्य कंक्रीट सामग्री की बर्बादी कम होती है।

राँची के लाइट हाउस प्रोजेक्ट का प्रस्तावित ढांचा।

ग्रीन पार्क एरिया और विवाह भवन का होगा निर्माण

ऑनलाइन समीक्षा कार्यक्रम के दौरान विभागीय सचिव श्री विनय कुमार चौबे ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर परियोजना स्थल के आसपास रह रहे लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए खेलकूद समेत अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित फुटबॉल ग्राउंड और सामाजिक कार्यों जैसे विवाह एवं अन्य सार्वजनिक समारोह के लिए करीब 500 लोगों की क्षमता वाला सामुदायिक भवन निर्माण करने का निर्देश परियोजना निर्माण एजेंसी को दिया है। साथ ही उन्होंने आवासीय परियोजना के 7 टावर्स के आसपास पांच ग्रीन एरिया पार्क विकसित करने का भी निर्देश दिया।

स्वयं सहायता समूह के संवर्धन, सशक्तिकरण एवं नए समूह के गठन के लिए पूरे राज्य में "SHG सप्ताह" का आयोजन

गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर झारखंड स्टेट अर्बन लाइवलीहुड डेवलपमेंट सोसाइटी (JSULDS) का गठन किया गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। DAY-NULM योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 50 नगर निकायों में अब तक कुल-12,355 स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। इन स्वयं सहायता समूहों का Profiling किया जाना आवश्यक है, जिससे कि साधनों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुल 4,500 स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है एवं इस हेतु स्वयं सहायता समूह से ही सक्रिय महिलाओं का भी पहचान किया जाना है। अतः SHG प्रोफाइलिंग से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में दिनांक 26.07.2021 से 01.08.2021 तक राज्य भर में **"SHG सप्ताह"** कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान राज्य के सभी नगर निकाय अंतर्गत गठित सभी स्वयं सहायता समूहों का Profiling का कार्य संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के Profiling हेतु सभी CMMs, COs, CRPs द्वारा कार्ययोजना तैयार कर कार्य संपन्न कराया जा रहा है। इसके अलावा इस विशेष सप्ताह के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आवंटित समूह गठन के लक्ष्य प्राप्ति के आलोक में निकाय अंतर्गत कुल समूहों में से सक्रिय महिलाओं की पहचान कर संलग्न लक्ष्य के अनुपात में निदेशालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश नगर निकायों को दिया गया है।

SHG सप्ताह कार्यक्रम के तहत रांची नगर निगम के विभिन्न वार्डों की तस्वीर।

SHG सप्ताह कार्यक्रम के दौरान निकाय द्वारा प्राप्त Best Picture, Best Success Story, Best Case Study, Best Innovation इत्यादि श्रेणी के **विजेता निकाय** की घोषणा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। निदेशालय द्वारा सक्रिय महिलाओं का तीन दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी कार्यरत सक्रिय महिलाओं का Participation Screening Cum Assessment का भी प्रशिक्षण दिया गया। SHG सप्ताह के क्रियान्वयन के संबंधित पहलुओं पर दिनांक-22.07.2021 एवं 23.07.2021 को सभी CMMs एवं COs के उन्मुखीकरण की व्यवस्था Google Meet के माध्यम से की गई।

कोडरमा नगर पंचायत | **जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति** | **फुसरो नगर परिषद**

राज्य के विभिन्न नगर निकायों की SHG Profiling की कुछ झलकियाँ।

क्षमता विकास पर जोर

डे-एनयूएलएम योजना के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट, नई दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा डे-एनयूएलएम योजना अंतर्गत SM&ID घटक पर योजना से जुड़े अधिकारियों के ''क्षमता निर्माण'' (Capacity Building) के लिए 22 जुलाई 2021 को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखण्ड के अलावे उड़ीसा, पं. बंगाल और नागालैंड आदि राज्यों के योजना से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड के सभी सिटी मैनेजर, सिटी मिशन मैनेजर एवं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेर ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डे-एनयूएलएम योजना के मुख्य उद्देश्य व सिटी मिशन मैनेजर की भूमिका व जिम्मेदारियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही योजना के क्रियान्वयन से संबंधित क्षेत्र स्तर पर आनेवाली समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया व की NMMU टीम द्वारा उन्हें हल करने का भरोसा दिलाया गया। SM&ID घटक के तहत SHG का गठन, पोषण व स्थिरता से संबंधित अनुभव का आदान-प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने डे-एनयूएलएम योजना के सभी घटकों की स्थिरता हेतु मानव संसाधनों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। स्वयं सहायता समूह एवं क्षेत्र स्तरीय संघों को रिवोल्विंग फण्ड (RF) प्रदान करने से संबंधित समस्यायों को भी NMMU टीम के साथ साझा किया गया।

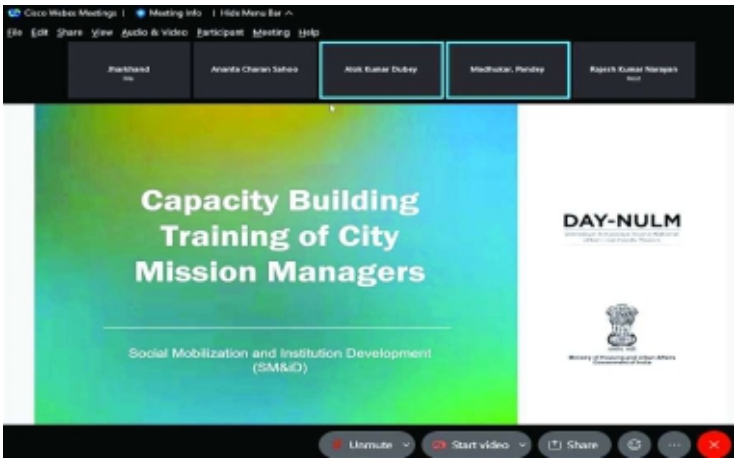

प्रशिक्षण के दौरान पीपीटी प्रेजेंटेशन।

प्रशिक्षण के दौरान पीपीटी प्रेजेंटेशन

प्रशिक्षण के दौरान पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से निम्नलिखित विषयों पर जानकारी प्रदान की गई:

1. योजना अंतर्गत CRPs रिक्रूटमेंट एवं संसाधन संगठन का प्रावधान (RO) पर विस्तृत निर्देश प्राप्त हुआ।
2. सूक्ष्म कार्य योजना से लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष जानकारी दी गई।
3. क्षमता निर्माण एवं हैंड होल्डिंग सपोर्ट की महत्ता पर चर्चा की गई।
4. CMMs की भूमिका पर खासतौर पर प्रकाश डाला गया।
5. समय से रिवोल्विंग फण्ड रिलीज करना, SHG का डेटा बैंक, शहरी सहभागिता मंच, सिटी लाइवलीहुड सेंटर के माध्यम से आजीविका को सुदृढ़ करने पर प्रकाश डाला गया।
6. पीएम सूक्ष्य उद्यम के विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण के अंत में नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट, नई दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा योजना से जुड़े अधिकारियों के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के उपरांत प्रशिक्षण के विभिन्न पहलूओं पर फीडबैक लिया गया और डे-एनयूएलएम प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा की गई।

कोरोना काल में काम न मिलने से थे बेरोजगार, MSY ने जीवन किया साकार

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) में निबंधित श्रमिक शंकर महतो।

शंकर महतो चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 35 के निवासी हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में निबंधित होने से पहले वे रोजाना खाने-कमाने वाले एक दैनिक मजदूर थे। दैनिक मजदूरी का काम मिलने पर ही उनके परिवार का भरण-पोषण हो पाता था।

इस काम में उन्हें हर दिन काम मिल ही जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी। उनके साथ कई बार ऐसा भी होता था कि लगातार उन्हें काम के अभाव में कई दिनों तक खाली बैठकर दिन गुजारना पड़ता था। इस वजह से उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में कई बार उन्हें व उनके परिवार को आधे पेट खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान काम न मिलने के कारण उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। ऐसे समय में शंकर महतो को DAY-NULM योजना को सीआरपी द्वारा झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में पता चला। तब उन्होंने जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया, जिसके बाद उन्हें इस योजना के तहत चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत चल रहे भवन निर्माण में श्रमिक का काम मिल गया।

इस योजना में निबंधित होने के परिणामस्वरूप उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी भी मिल गई, जिससे उन्हें व उनके परिवार को काफी सुकून मिला। इस प्रकार उनकी रोज-रोज की चिंता भी दूर हो गई। इसके लिए शंकर महतो व उनके परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को श्रमिकों के हित में बताते हुए तहे दिल से राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।

टाउन वेंडिंग समिति (TVC) के सदस्यों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि से मिलेगा सहयोग

राज्य के सभी नगर निकायों के टाउन वेंडिंग समिति के सदस्यों को शुक्रवार दिनांक 23.07.2021 को पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि से समृद्धि के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त निदेशक डॉक्टर अंजुली मिश्रा ने दिया।

इस दौरान बताया गया कि वैसे स्ट्रीट वेंडर जो निगम क्षेत्र में 24 मार्च 2020 के पूर्व व्यवसाय करते थे उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित फुटपाथ दुकानदारों को आजीविका चलाने के लिए बैंकों से कार्यकारी ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस निमित्त 15 अगस्त तक **''संकल्प से सिद्धि''** कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित TVC सदस्य (देवघर नगर निगम की तस्वीर)।

राज्य के तीन शहरों में की गयी ''संकल्प से सिद्धि'' अभियान की शुरुआत

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत '**संकल्प से सिद्धि**' **(Special Drive)** का आयोजन देश के 125 चयनित शहरों में किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के लिए झारखण्ड के भी तीन शहरों-रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद का चयन किया गया है। झारखण्ड में संकल्प से सिद्धि' कार्यक्रम दिनांक-01 जुलाई से 15 अगस्त, 2021 तक चलाया जायेगा। 'संकल्प से सिद्धि' कार्यक्रम के तहत राज्य के तीनो शहरों में जिन फुटपाथ विक्रेताओं का ऋण आवेदन किसी कारण से अस्वीकृत या रद्द हो गया है, वैसे आवेदनों की पुनः समीक्षा कर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना, ऋण प्राप्त कर चुके फुटपाथ विक्रेताओं एवं उनके परिवार को अन्य केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए परिवार के सदस्यों की एक पूरी प्रोफाइल तैयार करना, फुटपाथ विक्रेताओं को '**मैं भी डिजिटल**' कार्यक्रम के अंतर्गत कैशलेश लेन-देन के लिए प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहित करना, खाद्य पदार्थ पथ विक्रेताओं को FSSAI सर्टिफिकेट दिलाने एवं Swiggy तथा Zomato से लिंक करवाने के साथ-साथ फुटपाथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना के लाभ जैसे योजना अंतर्गत ₹ 10,000/- का तत्काल ऋण, पहले 12 माह के लिए फिर ₹ 20,000/- ऋण एवं समय पर वापस करने पर रु. 50,000/- का सिक्योरिटी फ्री लोन एवं नियमित भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी और कैशलेश लेन-देन करने पर 1200/- रुपये तक कैशबैक इत्यादी से अवगत कराने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

''कार्यक्रम के अंतर्गत फुटपाथ विक्रेताओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा-प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, BOCW अंतर्गत निबंधन, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं रूपये कार्ड इत्यादी से भी जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। रांची नगर निगम अंतर्गत 1005 फुटपाथ विक्रेताओं की डेटा बैंक, एवं ब्रांच भ्रमण की तिथि के साथ SLBC में प्रेषित की गई है, जिसे कोविड-19 अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए ऋण आवेदनों का निस्तारण किया जा सके।''

प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करेगा रांची नगर निगम

कचरा निस्तारण के लिए यूएनडीपी से बहुत जल्द होगा महत्वपूर्ण करार

आम के आम, गुठली के दाम। यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इसी कहावत पर अमल व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल करने जा रहा है रांची नगर निगम। जी हां, आने वाले कुछ दिनों में नगर निगम प्लास्टिक के कचरे से टी-शर्ट, कुर्सी, मग और ट्रे आदि बनाएगा।

भविष्य को संवारने की इस महत्वाकांक्षी योजना पर नगर निगम ने अपने कदम आगे बढ़ा भी दिए हैं। प्रदेश की राजधानी रांची के कचरा निस्तारण की इस योजना के तहत रांची नगर निगम व यूएनडीपी (यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम) के बीच एक करार किया जाएगा। इस करार के बाद नगर निगम यूएनडीपी के सहयोग से रांची में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए यूनिट लगाएगा। इसके लिए निगम की तरफ से यूएनडीपी को जमीन के साथ-साथ प्लास्टिक कचरा भी मुहैया कराया जाएगा। यूनिट लगाने का सारा खर्च यूएनडीपी उठाएगा। इस पर लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस यूनिट में प्लास्टिक कचरे से थ्रेड बनाया जाएगा। इसी थ्रेड से टी-शर्ट बनेगी।

इस संबंध में यूएनडीपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने नगर आयुक्त के साथ पिछले दिनों हुई मीटिंग में उनके द्वारा बनाए गए इस तरह के उत्पाद के कुछ नमूने भी दिखाए। उनका कहना था कि प्लास्टिक कचरे से वे प्लास्टिक की कुर्सियां, मग और बाल्टी आदि भी बनाएंगे।

पीएम स्वनिधि ने जगाई नई आस, योजना का लाभ बढ़ा रहा है लोगों का आत्मविश्वास

रितेश कुमार, पिता रामचंद्र राम, मेदिनीनगर नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 15 के निवासी हैं, जिनकी लॉकडाउन से पहले छोटी, लेकिन एक टिकाऊ दुकान बैंक ऑफ इंडिया, मेदिनीनगर के सामने रेडमा में स्थित थी। उसी दुकान से होनेवाली कमाई से उनके पूरे परिवार का खुशी-खुशी गुजारा हो रहा था। यह दुकान ही रितेश के परिवार की स्थायी आजीविका का स्रोत है। मगर कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन से उनका यह दुकान बंद हो गया। इस दौरान उनकी जमा-पूंजी का एक-एक पैसा परिवार के दैनिक कार्यों में खर्च हो गया। धीरे-धीरे उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होती गई। रितेश के मुताबिक, उस दौरान उनकी माली हालत और एक भिखारी जैसी हो गई थी। जब लॉकडाउन हटा तो वे एक तरह से सड़क पर आ गए थे।

पूर्ण लॉकडाउन के बाद जब आंशिक रूप से लॉकडाउन हटा तो उनके पास अपनी दुकान को फिर से चालू करने के लिए कोई पूंजी नहीं थी। उनके सामने अपनी एक छोटी सी दुकान का सिर्फ ढांचा खड़ा था। उन्होंने सचमुच बाजार में अपने आप को स्थापित करने की आशा खो

दी थी। उनके मन में तरह-तरह के नकारात्मक विचार आने लगे थे, लेकिन एक दिन मेदिनीनगर नगर निगम के एक अधिकारी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें फुटपाथ दुकानदारों व विक्रेताओं के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बताया। उन्होंने कर्मचारियों की मदद से ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके बाद उन्हें इस योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया, रेडमा शाखा, मेदिनीनगर से 10,000/- रुपये का ऋण मिला। रितेश को उनके ऋण और QR कोड आधारित डिजिटल लेन-देन के समय पर पुनर्भुगतान के लाभ के बारे में भी बताया गया। इस ऋण को प्राप्त करने के बाद फिर से रितेश की रूकी हुई जिंदगी पटरी पर आ गई और उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो गई। जो भी उम्मीद उन्होंने कुछ समय पहले खो दी थी, वह फिर से उनके मन में जगने लगी। उनके मन में आए सारे नकारात्मक सोच ने सकारात्मकता का रूप ले लिया था। इसके लिए रितेश ने मेदिनीनगर नगर निगम के कर्मचारियों का धन्यवाद प्रकट किया है।

सफलता की कहानी लाभुक की जुबानी

दुर्गा सुलंकी, पति-मोती सोलंकी, चाईबासा के वार्ड नंबर 21 की निवासी हैं। उनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। वह आदिवासी जनजाति समुदाय की एक सदस्य हैं। वे पिछले सात वर्षों से शहर के सुभाष चौक, टुंगरी में फुटपाथ पर समोसा-चाय की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं। उनका पूरा परिवार इसी दुकान पर आश्रित है, परन्तु कोरोना काल में लगे पूर्ण लॉकडाउन के कारण उन्हें लंबे समय तक अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। इस दौरान पूरी तरह से कमाई बंद होने के कारण परिवार के खर्च को पूरा करने में उनकी सारी जमा-पूंजी खत्म हो गई। लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू होने पर पूंजी का इंतजाम करना और फिर से अपना रोजगार शुरू करना मुश्किल लग रहा था। `से में आगे भविष्य का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान दुर्गा सुलंकी ने अपने क्षेत्र स्वयं सहायता समूह, टुंगरी की साप्ताहिक बैठक में शामिल हुई, जिसमें सीआरपी दीदी भी उपस्थित थीं। इस बैठक में दीदी द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ दुकानदारों व विक्रेताओं को सरकार द्वारा ऋण दिए जाने के बारे में जानकारी मिली। इसके साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी दी गई कि इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए बैंक की तरफ से 10,000 रुपये का आसान किस्तों में लोन दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें सरकार की तरफ से ब्याज में 7 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाती है। इस बारे में दुर्गा ने अपने पति से विचार-विमर्श कर ऋण लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया, जिसके उपरांत यह लोन बैंक से स्वीकृत होकर प्रदान कर दिया गया। इस लोन से उन्होंने चाय-समोसा की दुकान को फिर से शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उनकी दुकान फिर से पहले ही जैसी चलने लगी। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। इससे वह समय से लोन की किस्त जमा करने लगी। अब दुर्गा लोन की पूरी किस्त को जमा करने के बाद अगली बार 20,000 का लोन लेना चाहती हैं ताकि अपनी दुकान में थोड़ी पूंजी लगाकर उसका और अच्छी तरह से संचालन कर सके। दुर्गा का कहना है कि यह योजना उसके जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। अन्य फुटपाथ दुकानदारों को भी इस योजना का लाभ लेना चाहिए ताकि कोरोना महामारी के कारण उनकी जिंदगी की रूकी हुई गाड़ी भी पटरी पर आ सके और उनके परिवार में फिर से खुशहाली आ सके।

« जमशेदपुर अक्षेस की नई पहल »

जिओ टैगिंग के माध्यम से हल होंगी स्ट्रीट लाइट व चापाकल की समस्याएं

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) आम लोगों को बेहतर से बेहतर नागरिक सुविधा मुहैया कराने की दिशा में प्रयासरत व अग्रसर है। इस कड़ी में अब वह स्ट्रीट लाइट व चापाकल में जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) लगाने जा रही है। जीपीएस की मदद से लोगों को अब स्ट्रीट लाइट व चापाकल खराब होने की शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंधित एजेंसी को खुद-ब-खुद पता चल जाएगा कि किस स्थान पर स्ट्रीट लाइट खराब है या कहां चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। इसके साथ ही चोरी की घटना पर भी विराम लगेगा। किसी समाज विरोधी तत्व के द्वारा यदि स्ट्रीट लाइट या चापाकल का सामान चोरी किया जाता है, तो जीपीएस के माध्यम से संबंधित एजेंसी को इस बात का तुरंत पता चल जाएगा कि उस स्थान पर कुछ गड़बड़ी हो रही है।

साकची पार्किंग के पीछे शिफ्ट होगा मंगलाहाट: जमशेदपुर शहर स्थित मंगलाहाट साकची पार्किंग (बसंत टॉकीज के समीप) के पीछे स्थानांतरित (शिफ्ट) होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की पहल और जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने मंगलाहाट लगाने के लिए साकची पार्किंग के पीछे स्थान तय किया है। इसके लिए जेएनएसी जमीन के समतलीकरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही साकची बाजार में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर काफी समय से चल रहे विवाद का भी समाधान हो गया है। जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार, सिटी मेनेजर रवि भारती आदि ने नए स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व में दुकानदारों को साकची आम बागान मैदान ले जाने का निर्देश दिया गया था। साकची बाजार से दूर रहने और ग्राहकों के नहीं आने से दुकानदार वहां नहीं गए। जिला प्रशासन ने जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए साकची बाजार में फुटपाथ पर दुकानों को लगाने से रोक दिया गया था।

खुद चालू और बंद होंगी स्ट्रीट लाइट

आने वाले दिनों में जमशेदपुर शहर की सभी स्ट्रीट लाइट खुद चालू होंगी और खुद ही बंद हो जाएंगी। इसके लिए सभी स्ट्रीट लाइट्स को ग्राउंड पोजीशिनिंग सिस्टम (जीपीएस) से जोड़ा जाएगा। इस नई व्यवस्था से दिन में स्ट्रीट लाइट जलने की समस्या और बिजली की अतिरिक्त खपत से मुक्ति मिलेगी। शहर के किसी भी इलाके में कोई भी स्ट्रीट लाइट खराब होती है, तो कंट्रोल रूम को लोकेशन के साथ इस बात का पता चल जाएगा कि किस इलाके में लाइट नहीं चल रही है। जीपीएस के लागू होने से बिजली की भी बचत होगी। वर्तमान में शहर में कहीं दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, तो तुरंत इसका पता नहीं चल पाता है। मगर जीपीएस के लागू होने से सभी स्थानों पर जरूरत के अनुसार ही स्ट्रीट लाइट जलती हुई मिलेगी।

PMAY (U) से हुआ जीवन का अधूरा सपना पूरा

मनुष्य की जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वह है-रोटी, कपड़ा और मकान। इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं एवं अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए मनुष्य अपने जीवनकाल का अधिकतर समय अथक एवं संघर्षशील प्रयासों में लगा देता है। जी हां, आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्स के संघर्षशील जीवन से रू-ब-रू कराने जा रहा हूं जो अपनी इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का सपना सदियों से बेसब्र निगाहों से देखा करता था। उस शख्स का नाम है-श्रीमती जमीला बीबी, पति श्री हद्रीश खलीफा। उनकी उम्र 45 वर्ष है व वह नगर उंटारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की निवासी हैं। श्रीमती जमीला बीबी के परिवार में उनके पति समेत कुल पांच लोग हैं जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं।

श्रीमती जमीला बीबी के पति इंद्रीश खलीफा का पेशा कपड़े की सिलाई यानि दर्जी का है जो उन्हें विरासत में अपने पूर्वजों से मिला है। इंद्रीश खलीफा यह काम एक छोटे से दुकान में किया करते थे। इस काम में उनकी पत्नी भी उनका सहयोग करती थीं। यह दुकान उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर नगर उंटारी के नजदीक विख्यात वंशीधर मंदिर के निकट स्थित था। यहां ये प्रतिदिन सिलाई का काम कर तथा उसी से अपना जीविकोपार्जन कर अपने झोपड़ीनुमा कच्चे घर में किसी तरह परिवार समेत जीवन का गुजारा कर रहे थे। यह मकान किसी भी मौसम के अनुकूल नहीं था, जिसमें उनके परिवार के कुल पांच सदस्य एक साथ रहते थे।

चुंकि इंद्रीश खलीफा जी के परिवार की माली हालत अपना पक्का मकान बनाने के लायक नहीं थी, इसलिए वे झोपड़ीनुमा खपरैल/कच्चे मिट्टी के घर में रहने को मजबूर थे। उनकी आजीविका जैसे-तैसे चल रही थी कि वर्ष 2017 में उनके जीवन में एकाएक उस समय उम्मीद की किरण नजर आई जब उन्हें इस बात का पता चला कि सरकार गरीबों को पक्का मकान बनाने हेतु सहायता राशि प्रदान कर रही है। यह जानकारी इनके ग्राहकों ने ही बातों-बातों में उन्हें बताई। तब उन्होंने अपने ग्राहकों से ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने उनसे इसके आवेदन-पत्र में लगने वाले कागजात के संबंध में पूरी जानकारी ली। अपने शिक्षित एवं जागरूक ग्राहकों की मदद से इंद्रीश खलीफा जी ने अपनी पत्नी श्रीमती जमीला बीबी (लाभुक) के नाम से सारे कागजात तैयार किरातश्वाक तु ई घटक केहता नगर निकाय कार्यालय में अपना आ ेदन जमा किया। चार माह के बाद एकाएक उनके जीवन में खुशियों का आशियाना बन जाने का सपना सच होता हुआ लगने लगा जब उन्हें किसी ग्राहक ने बताया कि उनके आवास की स्वीकृति मिल गई है। इस खबर को सुनकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने उस ग्राहक से मिलकर उन्हें तहेदिल मुबारकबाद दी। श्रीमती जमीला बीबी ने कहा कि यह लम्हा उनके जीवन के सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक था, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि अब उनका भी खुशियों का अपना आशियाना होगा। इसी कड़ी में उन्होंने आवास स्वीकृति उपरांत नगर निकाय कार्यालय में जाकर एकरारनामा कर अपने आवास निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया। घर के सभी सदस्यों ने निर्माण कार्य में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य में सिर्फ एक राजमिस्त्री की सहायता ली।

निर्माणाधीन आवास

पूर्ण आवास

सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित होकर इनका पूरा परिवार आज जिन्दगी के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया जहां इनकी खुशियों का अपना आशियाना बनकर तैयार था जो हर मौसम में सुकून और शांति से रहने के लिए अनुकूल था।

पारदर्शिता की ओर बढ़ाएं कदम, जवाबदेही का मूल्य अपनाएं हम

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता लाने, जवाबदेही एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने व उसे और ज्यादा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार द्वारा जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की प्रक्रिया शुरू की गई. सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य के 9 जिलों के (शहरी निकायों) का चयन किया गया।

इनमें धनबाद, गढ़वा, बासुकिनाथ, मधुपुर, दुमका, चक्रधरपुर, रामगढ़, सिमडेगा और लोहरदगा शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित सामाजिक सर्वेक्षण यूनिट (Social Audit Unit) को इस कार्य की जिम्मेवारी सौंपी गई है। नगरीय प्रशासन निदेशालय के साथ संयुक्त रूप से इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रपत्र विकसित किया गया है। जिसके तहत 5 अगस्त तक विभिन्न चरणों में आवास निर्माण की समीक्षा की जाएगी। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सामाजिक अंकेक्षण इकाई की ओर से दो दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से सम्बंध रखने वाले सिटी मैनेजर, सीएलटीसी स्पेशलिस्ट और सोशल ऑडिट इकाई के सदस्य शामिल हुए। वेबिनार में शामिल लोगों को सोशल ऑडिट के स्टेट को-ऑर्डिनेटर गुरमीत सिंह ने सोशल ऑडिट की पूरी प्रक्रिया की जानकारी वेबिनार में उपस्थित अधिकारियों को दी। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जिओटैगिंग, लाभुक का चयन, किए गए कार्य के विरूद्ध किस्त का भुगतान, कार्य की गुणवत्ता, ग्रीन कार्ड की उपलब्धता और तकनीकी कार्य आदि की जांच की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माण क्षेत्र में बिजली, पेयजल व शौचालय के साथ-साथ इनकी उपयोगिता की भी समीक्षा की गई।

राज्य के 9 नगर निकायों में PMAY (U) की सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया शुरू

सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम (गढ़वा नगर परिषद की तस्वीर)।

मछुवा समुदाय के 250 परिवारों के जीवन में बहार बनकर आई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना

बुण्डू नगर पंचायत की शान कहे जाने वाले बुण्डू बड़ा तालाब न केवल आर्थिक व सामाजिक रूप से, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अपने आप में काफी महत्व रखता है। इस तालाब पर बुण्डू की लगभग 40% आबादी किसी न किसी रूप में निर्भर करती है। यह तालाब लगभग 100 एकड़ भूमि में स्थित है। इस तालाब में मुख्य रूप से मछली पालन, सिंचाई, स्नान एवं कई तरह के दैनिक कार्यों का निष्पादन बुण्डू शहरवासी करते हैं। बुण्डू बड़ा तालाब की अपनी एक अलग पहचान है। बुण्डू के बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि इस तालाब का पानी कभी भी नहीं सूखता है जो अपने आप में एक अचरज वाली बात लगती है, परन्तु यह बात सत्य है।

बुण्डू के करीब 250 मछुआ परिवार अपनी आजीविका के लिए इस तालाब पर आश्रित हैं, परंतु विगत कई वर्षों से इस तालाब में काफी मात्रा में जलकुंभी का जमावड़ा हो गया था, जिसके कारण इस तालाब की खूबसूरती और इसपर आश्रित 250 परिवारों की आजीविका (रोजी-रोटी) प्रभावित हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में काफी संख्या में मछुवा परिवार के लोग आजीविका के लिए पलायन को मजबूर हो गए थे। इस तालाब पर आश्रित मछुवा समुदाय के कई लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पं. बंगाल, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, दिल्ली जैसे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो गए थे। इन लोगों के बीच काफी निराशा भरे हालात पैदा हो गए थे। ऊपर से कोविड-19 के कारण परिस्थिति और भी बदतर हो गई थी। लोगों को काम मिलना मुश्किल हो गया था। रोजमर्रा की जिन्दगी में काफी कठिनाई सामने आ रही थी। ऐसे समय में गरीब परिवारों का भरण-पोषण मुश्किल हो गया था। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए नगर पंचायत, बुण्डू के माननीय अध्यक्ष श्री राजेश उरांव, माननीय वार्ड पार्षद श्री चन्दन मछुवा व माननीय कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बुंडू, श्री अजय कुमार साव, सिटी मिशन मैनेजर एवं सिटी मैनेजर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन के द्वारा 14 अगस्त, 2020 को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के शुभारंभ के पश्चात सभी अकुशल श्रमिकों का जॉब कार्ड बनवाया गया। साथ ही इस तालाब की सफाई कराने हेतु एक योजना तैयार की गई। जिसके उपरांत तालाब की सफाई के कार्य का शुभारंभ किया गया। योजना की मदद से बाहरी राज्यों से अपने राज्य में आए प्रवासी मजदूरों को भी अपने घर के पास ही काम मिल गया, जिससे उनमें खुशी का माहौल है। करीब 250 मछुवा परिवार, जिनका मुख्य व्यवसाय मछली पालन है एवं अपनी आजीविका के लिए वे पूरी तरह से उसी पर निर्भर हैं।

तालाब की सफाई और जल कुम्भी निकालते MSY योजना में निबंधित श्रमिक (बुण्डू बड़ा तालाब)

वर्तमान समय में बुण्डू में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत रोड व नाली निर्माण समेत कई अन्य योजनाओं में काम जारी है। इनमें स्थानीय श्रमिकों को काम मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत बुण्डू में कुल 647 जॉब कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त किया गया है, जिसमें से 298 आवेदकों का जॉब कार्ड बनाया गया एवं 185 कार्यों की मांग की गई है, जिसमें से सभी को काम दे दिया गया है।

MSY ने श्रमिकों की तकदीर व शहर की तस्वीर बदली

बड़की सरैया नगर पंचायत अंतर्गत सफाई का कार्य करते MSY में निबंधित श्रमिक।

विश्व्यापी महामारी COVID-19 के दौरान लगे लंबे लॉकडाउन में भारी संख्या में बड़की सरैया नगर पंचायत के लोगों का रोजगार चला गया। देश के कई अन्य बाहरी प्रदेशों में यहां के जो मजदूर काम कर रहे थे, वे भी कोई काम नहीं मिलने के कारण अपने घर लौट आने को मजबूर हुए। अपने भविष्य के लिए बचाकर रखे गए उनके सारे पैसे भी लॉकडाउन के दौरान खर्च हो गए थे ऐसे समय में उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें बड़की सरैया नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई। साथ ही इन लोगों का जॉब कार्ड बनाकर इन मजदूरों को दिया गया। इनमें कई अकुशल मजदूर भी शामिल थे।

वर्तमान समय में ये सभी मजदूर युद्धस्तर पर नगर पंचायत क्षेत्र में नालियों की सफाई का काम कर रहे हैं गौरतलब है कि इन दिनों पूरे राज्य में सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार स्पेशल ड्रेन क्लीनिंग ड्राइव चलवाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान नालियों की सफाई का काम जोर-शोर से जारी है।

इस विशेष से अभियान श्रमिकों में ख़ुशी है उनका कहना है कि जहां नालियों की सफाई होने से हमारा पर्यावरण शुद्ध व स्वच्छ रहेगा, वहीं अब उन्हें बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। इसके लिए उन्होंने बड़की सरैया नगर पंचायत के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। इस योजना के निरीक्षण और देखरेख का काम नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मिशन मैनेजर, सिटी मैनेजर और सामुदायिक संगठनकर्ता के द्वारा किया जा रहा है।

बासुकिनाथ नगर पंचायत ने की "जल शक्ति अभियान" की शुरुआत

जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन के रूप में कार्य करने का लिया संकल्प

बासुकिनाथ पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। कार्यालय कर्मियों के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में जगह-जगह वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्हें यह बताया गया कि किस तरह वे वृक्षारोपण कर और जल बचाकर अपने भविष्य को और बेहतर कर सकते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम दौरान नगर पंचायत के कार्यालय कर्मियों ने सामूहिक तौर पर इस बात का संकल्प लिया कि बासुकीनाथ नगर पंचायत लोगों की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन के रूप में कार्य करेगी। मौके पर नगर पंचायत के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जन प्रतिनिधिगण, कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यालय कर्मी एवं ग्रामीण मौजूद थे।

12 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ऋण प्रक्रिया की समीक्षा

बैंकों को पीएम आवास के लाभुकों के लिए गृह ऋण के नियम आसान बनाने के निर्देश दिए गए।

पीएम आवास योजना के लाभुकों के लिए गृह ऋण की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-29.07.2021 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की हाउसिंग उपसमिति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में SLBC तथा प्रमुख बैंकों के राज्य प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गृह ऋण की समीक्षा निदेशक, डीएमए के द्वारा की गई। इसके साथ ही PMAY(U) के तहत निर्माण हो रहे किफायती आवास परियोजना (AHP) के लाभुकों को गृह ऋण प्रदान एवं ऋण प्रक्रिया को और सरल बनाने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गएकबैठक में विभिन्न नगर निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, एसबीआई समेत प्रमुख बैंकों के वरीय अधिकारी शामिल हुए।

बिरसानगर किफायती आवास परियोजना की भी जानकारी लीः पीएम आवास योजना के तहत बिरसानगर किफायती आवास परियोजना की भी समीक्षा की गई। बिरसानगर पीएम आवास योजना के 9 ब्लॉकों का निर्माण चल रहा है यहां कुल 9591 फ्लैट बनेंगे। अब तक 3571 लाभुकों ने बैंक में 5-5 हजार रूपये का चालान जमा कर आवेदन किया है। आम लोगों के बीच जागरूकता व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए निगम क्षेत्र में कार्यरत श्री राहुल कुमार, दीपक मांझी एवं सरिता कुमारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

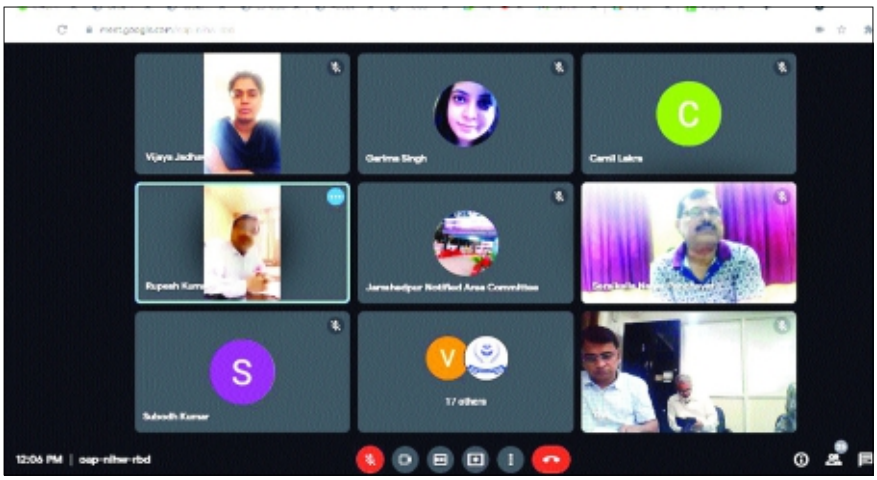

समीक्षा कार्यक्रम की वीडियो कांफ्रेंसिंग की तस्वीर।

कोयले का प्रचुर भंडार एवं पर्यटन की अपार संभावना : चतरा नगर परिषद

चतरा जंगलों से घिरा और हरियाली से भरा प्रकृति की गोद में बसा झारखण्ड प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले में खनिज के साथ कोयला भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला चतरा जिले की स्थापना 29 मई 1991 में हुई थी। एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले यह हजारीबाग जिले का एक उपखंड (अनुमंडल) हुआ करता था। चतरा जिले में दो अनुमंडल एवं 12 अंचल/प्रखंड तथा 154 पंचायत एवं 1474 राजस्व गाँव शामिल हैं। चतरा में एक नगर परिषद है जो चतरा जिला मुख्यालय में स्थित है।

कोल परियोजनाः आम्रपाली कोल परियोजना और मगध कोल परियोजना।

चतरा के प्रमुख पर्यटन स्थल : यहां सैलानी तरह के जंगली जीवों को देखने व हरियाली का आनंद उठाने दूर-दूर से आते हैं। इसके अलावा चतरा जिले में कई धार्मिक महत्व के स्थल भी मौजूद हैं जो यहां आने वाले लोगों के लिए विशेष आस्था के केंद्र हैं। इनमें भद्रकाली मंदिर, कोल्हुआ पहाड़, कौलेश्वरी मंदिर शामिल हैं।

पिकनिक स्पॉट : पठारीय जगह होने के कारण चतरा जिले में कई पिकनिक स्थल (पिकनिक स्पॉट) मौजूद हैं। इनमें तमासीन जलप्रपात, मालुदाह जलप्रपात, डुमेर-सुमेर जलप्रपात, गोवा जलप्रपात, कुंदा किला, बिचकिलिया जलप्रपात, दुवारी जलप्रपात, खैवा बंदारू जलप्रपात, केरिदाह जलप्रपात प्रमुख रूप से शामिल हैं।

एतिहासिक पर्यटन स्थल : भद्रकाली मंदिर

चतरा नगर परिषद एक नजर में

कुल क्षेत्रफल	कुल वार्डों की संख्या	कुल जनसँख्या	पुरूष :	महिला :
9.9 वर्ग किलोमीटर	22	49985	26555	23430

अध्यक्षः श्रीमती गुंजा देवी
उपाध्यक्षः श्री सुदेश कुमार
कार्यपालक पदाधिकारीः श्री सुरेंद्र सिंह

मोहरदा जलापूर्ति योजना।

अब बिना होल्डिंग नंबर वाले को भी मिलेगा पानी का कनेक्शनः जमशेदपुर अक्षेस

मोहरदा जलापूर्ति योजना का लाभ लेने से वंचित बिरसानगर, बारीडीह, बागुननगर, बागुनहातु के लगभग 5000 लोगों को जलापूर्ति योजना का लाभ दिलाने के लिए अब बिना होल्डिंग नंबर वालों को भी कनेक्शन वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने जुस्को को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा- निर्देश दिया है। जुस्को को निर्देश दिया गया है कि मोहरदा जलापूर्ति योजना का लाभ वैसे घरों में भी दिया जाए जिनका होल्डिंग नंबर नहीं है। विशेष पदाधिकारी के आदेश के बाद अब जल्द ही वैसे घरों में भी जलापूर्ति होने लगेगी जो वर्षों से नल का पानी का इंतजार कर रहे थे। पहले कुछ तकनीकि खामियों को लेकर असमंजस की स्थिति थी। अब चूंकि विभाग से सहमति मिलने के बाद जल्द ही वैसे घरों में पाइप लाइन से पानी मिलने लगेगा, जो मोहरदा जलापूर्ति योजना से वंचित अब जमशेदपुर अक्षेस के अंतर्गत लगभग 5000 घरों में इसका लाभ मिलेगा।

संरक्षक
श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री

संपादक
विनय कुमार चौबे
सचिव
नगर विकास एवं
आवास विभाग

कार्यकारी संपादक
विजया जाधव
निदेशक
नगरीय प्रशासन
निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास
विभाग

यह बुलेटिन विभाग के कार्यों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित है।

DAY-NULM योजना अन्तर्गत
राज्य के सभी नगर निकायों में स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन,
सशक्तिकरण एवं नए समूह के गठन हेतु जुलाई माह के अंतिम सप्ताह से
'SHG सप्ताह' का आयोजन किया गया है। इस दौरान सभी CMMs/COs/CRPs द्वारा
कार्ययोजना तैयार कर SHG Profiling का कार्य भी किया जा रहा है।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Follow us on : @JharkhandDMA , Website : www.dmajharkhand.in

1st Floor, JUPMI Building, Beside H.E.C Headquarter, Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand